

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

# विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, शनिवार, 31 जनवरी, 2025 ई0 (माघ 11, 1946 शक संवत्)

# कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-3754/दस-लाइसेंस-185/भांग फुटकर नियमावली, 2024-2025 प्रयागराज, दिनांक 31 जनवरी, 2025 ई0

# अधिसूचना

#### सा0प0नि0-08

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की अधिसूचना सं0 26743/दस-लाइसेंस-185/2018-2019 प्रयागराज/दिनांक-29 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2019 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2024

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)(तृतीय संशोधन) नियमावली, 2024 कही जायेगी।
  - (2) यह दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. नियम-8 का संशोधन— उत्तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2019 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् —

#### स्तम्भ-1

#### विद्यमान नियम

- (क) भारत का नागरिक हो, परन्तु भांग का थोक आपूर्तिकर्ता किसी फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने हेतु पात्र नहीं होगा। दुकान आवंटन के पश्चात आवेदक की स्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा,

परन्तु, लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंस की शेष अविध के लिए लाइसेंसधारी बना रह सकता है।

#### स्तम्भ-2

#### एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

- 8-आवेदकों के लिये पात्रता की शर्तें- फुटकर भॉग की दुकान के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी होगी- अर्थात्
- (क) भारत का नागरिक हो, परन्तु भांग का थोक आपूर्तिकर्ता किसी फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने हेतु पात्र नहीं होगा। दुकान आवंटन के पश्चात आवेदक की स्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा,

इच्छुक फुटकर और थोक लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस के अंतरण के संबंध में एक नामनिर्देशन शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि वरीयता क्रम में अपने वारिसों/परिवार के सदस्यों/निकट संबंधियों का नाम, आधार संख्या, संबंध आदि का उल्लेख किया जा सकता है। मृत्यु के प्रकरणों में सर्वप्रथम नामनिर्देशन शपथ पत्र के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जायेगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाई की जायेगी। उक्त नामनिर्देशन नोटरीकृत शपथ पत्र पर लाइसेंस प्राधिकारी के कार्यालय में विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा।

परन्तु यह कि लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंस की शेष अविध के लिए लाइसेंसधारी बना रह सकता है।

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती वर्षों से नवीकृत होती आ रहीं दो लाइसेंसों वाली दुकानों के मामलों में नवीकरण के पूर्व ही किसी एक लाइसेंधारी की मृत्यु हो जाती है तथा उसके विधिक वारिस अथवा नामनिर्देशिती आवेदन नही देता है अथवा वह अनुपयुक्त पाया जाता है तो, आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अन्य जीवित लाइसेंधारी के पक्ष में सम्बन्धित वर्ष हेतु दुकान की संपूर्ण प्रतिभूति, विहित दिनांक तक जमा करने के निर्वंधन के साथ दुकान का नवीकरण किया जाना अनुमन्य होगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उस वर्ष की जमा प्रतिभूति नियमानुसार वापस की जायेगी।

परन्तु यह और भी कि यदि पूर्ववर्ती वर्षों से नवीकृत होती आ रहीं दो जीवित लाइसेंधारी वाली दुकानों का नवीकरण केवल दोनों ही लाइसेंधारियों के मध्य सहमति की दशा में ही किया जायेगा। सहमति के अभाव में नवीकरण किया जाना अनुमन्य नही होगा।

- (ख)आवेदन करने के समय आवेदनकर्ता की आयु इक्कीस वर्ष से अधिक हो।
- (ग) व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित अथवा अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के उपबंधों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय द्वारा किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।
- (घ) आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिए स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा।
- (ङ) निम्नलिखित की पृष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-
- (एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।
- (दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
- (तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चिरत्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो।
- (चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के जिला कलक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस किमश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट, सहायक पुलिस आयुक्त के रैंक के अनिम्न अधिकारी, द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।

## स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (ख) आवेदन करने के समय आवेदनकर्ता की आयु इक्कीस वर्ष से अधिक हो।
- (ग) व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित अथवा अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के उपबंधों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय द्वारा किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।
- (घ) आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिए स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा।
- (ङ) निम्नलिखित की पृष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-
- (एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।
- (दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
- (तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषिध एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो।
- (चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के जिला कलक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस किमश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट, सहायक पुलिस आयुक्त के रैंक के अनिम्न अधिकारी, द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।

- (पॉच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से अपने प्राधिकृत बिक्रीकर्ता/ प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा।
- (छः) यह कि उस पर कोई लोक देयता या सरकारी देयता का बकाया नहीं है।
- (सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।
- (आठ) यह कि आवेदक सिक्रिय रूप से माफिया गितविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गितविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस जारी हो जाने के पश्चात् भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सिक्रिय रूप से माफिया गितविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गितविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया लाइसेंस रदद् कर दिया जायेगा।
- (नौ) यह है कि आवेदक बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस रदद् कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी, लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अनर्ह होगा।
- (दस) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चियनत हो जाने पर चयन के 48 घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे ऑन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया है, को उसके द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।
- (ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नही किया है।
- (च) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के नाम से बना हो, की स्कैन प्रति आनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा;

### स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (पॉच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से अपने प्राधिकृत बिक्रीकर्ता/ प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा।
- (छः) यह कि उस पर कोई लोक देयता या सरकारी देयता का बकाया नहीं है।
- (सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।
- (आठ) यह कि आवेदक सिक्रय रूप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस जारी हो जाने के पश्चात् भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सिक्रय रूप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया लाइसेंस रदद् कर दिया जायेगा।
- (नौ) यह है कि आवेदक बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस रदद् कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी, लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अनहीं होगा।
- (दस) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चियनत हो जाने पर चयन के 48 घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे ऑन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया है, को उसके द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।
- (ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नही किया है।
- (च) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के नाम से बना हो, की स्कैन प्रति आनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा;

- (छ) लाइसेंसधारी के रूप में चियनत हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात् 48 घण्टे के भीतर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसे दुकान की सभी देयताओं के भुगतान के पश्चात् वापस कर दिया जायेगा;
- (ज) आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा जारी धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता/प्राधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा जारी धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिये अवधारित लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिला में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर वेल्युअर द्वारा जारी धारित संपत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करे, जहां से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया है:

परन्तु नवीकरण की स्थिति में, गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि यह वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे;

## स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (छ) लाइसेंसधारी के रूप में चियनत हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात् 48 घण्टे के भीतर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसे दुकान की सभी देयताओं के भुगतान के पश्चात् वापस कर दिया जायेगा;
- (ज) आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा जारी धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता/प्राधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा जारी धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिये अवधारित लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिला में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर वेल्युअर द्वारा जारी धारित संपत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करे, जहां से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया है;

परन्तु नवीकरण की स्थिति में, गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि यह वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे;

3-नियम-12 का संशोधन- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

#### स्तम्भ-1 विद्यमान नियम

12 -लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का संदेय यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो वह अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयनित होने की सूचना के दस कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के बीस कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि सावधि जमा रसीद /बैंक गारंटी के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई-पेमेण्ट द्वारा जमा की जायेगी।

# स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

12 -लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का संदेय यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रूप में चयनित किया जाता है तो वह अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयनित होने की सूचना के दस कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के बीस कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि सावधि जमा रसीद /बैंक गारंटी के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई-पेमेण्ट द्वारा जमा की जायेगी।

परन्तु, यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन रद्द हो जायेगा:

परन्तु यह और कि ई लाटरी/ई टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का पन्द्रह प्रतिशत तथा नवीकरण फीस व लाइसेंस फीस, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

# स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

परन्तु यह कि प्रतिभूति धनराशि विहित अविध के भीतर जमा नहीं की जाती है तो, रु. 2000/- प्रति दिवस की दर से शास्ति अधिरोपित होगी। शास्ति सहित प्रतिभूति धनराशि जमा करने हेतु मात्र 15 दिवस की अविध अनुमन्य होगी।

परन्तु, यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन रद्द हो जायेगा;

परन्तु यह और कि ई लाटरी/ई टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का पन्द्रह प्रतिशत तथा नवीकरण फीस व लाइसेंस फीस, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

4-नियम-20 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-**20** के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

#### स्तम्भ-1 विद्यमान नियम

#### 20- दुकानों का अन्तरिम व्यवस्थापन -

(1) इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निलम्बन, निरस्तीकरण, अभ्यर्पण या अन्य किसी कारण से दकान अव्यवस्थित होने के मामले में लाइसेंस प्राधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिस्चित ऐसी दरों पर दैनिक लाइसेंस फीस और समान्पातिक प्रतिफल फीस (अर्थात दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस), जो कि एक बार में अधिकतम चौदह दिनों की अवधि या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक इसमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी, के संदाय पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन सर्वोच्च आफर पर कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने के मामले में सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि में निहित प्रतिफल फीस तथा लाइसेंस फीस के योग की 1/6 धनराशि के बराबर की प्रतिभृति धनराशि जमा करना होगा। लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी दुकान का ऐसा व्यवस्थापन दो से अधिक बार किया जा सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त को सूचित करना अनिवार्य होगा।

# स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

#### 20- दुकानों का अन्तरिम व्यवस्थापन -

(1) इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निलम्बन, निरस्तीकरण, अभ्यर्पण या अन्य किसी कारण से दकान अव्यवस्थित होने के मामले में लाइसेंस प्राधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिस्चित ऐसी दरों पर दैनिक लाइसेंस फीस और समानुपातिक प्रतिफल फीस (अर्थात दैनिक न्युनतम प्रत्याभृत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस), जो कि एक बार में अधिकतम चौदह दिनों की अवधि या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक इसमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी, के संदाय पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन सर्वोच्च आफर पर कर सकता है। एक द्कान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने के मामले में सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि में निहित प्रतिफल फीस तथा लाइसेंस फीस के योग की 1/6 धनराशि के बराबर की प्रतिभृति धनराशि जमा करना होगा। लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी दुकान का ऐसा व्यवस्थापन दो से अधिक बार किया जा सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त को सूचित करना अनिवार्य होगा।

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के	(2) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के
निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के मामले में दुकान का मध्यसत्र में	निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के मामले में दुकान का मध्यसत्र में
नियमित व्यवस्थापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र	नियमित व्यवस्थापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र
सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से	सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से
कराया जायेगा। उक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी	कराया जायेगा। उक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी
आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा।	आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा। <b>मध्य सत्र में</b>
	व्यवस्थापित की जाने वाली दुकानों के लिए ई-निविदा
	प्रक्रिया में एकल निविदा भी स्वीकार किये जायेगें।

डा0 आदर्श सिंह, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

#### OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, PRAYAGRAJ, UTTAR PRADESH

No. 3754/X-License-185/Bhang Retail Rules-2024-25

Prayagraj, dated: January 31, 2025

#### **NOTIFICATION**

In exercise of the powers under section 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no 4 of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no 1 of 1904) the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government **is pleased to** makes the following rules with a view to **amend** the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Retail Sale of Bhang) Rules, 2019 published *vide* Notification no. 26743/X-Licence 185/2018-2019/dated: January 29, 2019, **namely:**—

# THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENSES FOR RETAIL SALE OF BHANG) (THIRD AMENDMENT) RULES, 2024

- 1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of licenses for Retail Sale of Bhang) (**Third** Amendment) Rules, **2024.** 
  - (2) They shall be deemed to have come into force with effect from 01st April, 2024.
- 2. Amendment of rule—(2) In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Retail Sale of Bhang) Rules, 2019 hereinafter referred to as the said rules, for rule 8 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:—

#### Existing rule

- 8. Eligibility conditions for applicants:- eligible applicants for license of a retail bhang shop must fulfill follwing conditions, namely:-
- (a) be a citizen of India, but whole sale supplier of Bhang shall be not eligible for holding license of any retail shop. No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop;

Provided, in the event of death of licensee, his/her legal heir, if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license;

#### Column-II

#### Rule as hereby substituted

- 8. Eligibility conditions for applicants:- eligible applicants for license of a retail bhang shop must fulfill follwing conditions, namely:-
- (a) be a citizen of India, but whole sale supplier of Bhang shall be not eligible for holding license of any retail shop. No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop;

A nomination affidavit can also be submitted by the interested retail and wholesale licensee regarding the transfer of license in which he can mention the name of his heirs/family members/close relatives, Aadhaar number, relation etc. in first, second, third etc. order of preference. In cases of death, the applications submitted as per the nomination affidavit will be considered first, otherwise action will be taken as per the rules. The said nomination will be submitted in the prescribed format in the office of the licensing authority on a notarized affidavit:

Provided **that** in the event of death of licensee, his/her legal heir, if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license:

Provided further that in the case of shops with two licenses which have been renewed since previous years, if one of the licensees dies before renewal and his legal heir or nominee does not submit the application or is found unsuitable, then on receipt of the application, renewal of the shop for the concerned year in favour of the second surviving licensee will be permissible with the restriction depositing the entire security of the shop by the prescribed date. At the end of the financial year, the security deposit of that year will be returned as per rules.

Column-I
Existing rule

# **Column-II**Rule as hereby substituted

Provided also that if the shops with two surviving licensees which are getting renewed since previous years, will be renewed only in the case of consensus between both the licensees for renewal. In

the absence of consensus, renewal will not

be permissible.

- (b) be above twenty-one years of age at the time of making application;
- (c) not be defaulter/blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions of any rules made under act. Any person who has been convicted of any excise offence by any court of law unless fully and finally acquitted shall be automatically debarred from holding the license;
- (d) applicant shall be eligible for making only one application in his own name for any shop
- (e) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely:-
- (i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premise in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop, Rules, 1968 as amended from time to time:
- (ii) that his proposed premise of the shop has not been constructed in violation of any law or rules;
- (iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under United Provinces Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence;

- (b) be above twenty-one years of age at the time of making application;
- (c) not be defaulter/blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions of any rules made under act. Any person who has been convicted of any excise offence by any court of law unless fully and finally acquitted shall be automatically debarred from holding the license;
- (d) applicant shall be eligible for making only one application in his own name for any shop
- (e) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely:-
- (i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premise in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop, Rules, 1968 as amended from time to time;
- (ii) that his proposed premise of the shop has not been constructed in violation of any law or rules;
- (iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under United Provinces Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence;

#### Existing rule

- (iv) that in case of being selected as licensee he will furnish a certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate of the district of which he is resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license;
- (v) that he shall not employ any salesmen or representative who has criminal background as mentioned in clauses (iii) or who suffers from any infectious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman/representative from District Excise Officer;
- (vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues;
- (vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds, for conducting the business, the details of which shall be made available to the licensing authority if required;
- (viii) that applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities. If after issuance of license it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted license shall be cancelled;

#### Column-II

#### Rule as hereby substituted

- (iv) that in case of being selected as licensee he will furnish a certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate of the district of which he is resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license;
- (v) that he shall not employ any salesmen or representative who has criminal background as mentioned in clauses (iii) or who suffers from any infectious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman/representative from District Excise Officer;
- (vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues;
- (vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds, for conducting the business, the details of which shall be made available to the licensing authority if required;
- (viii) that applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities. If after issuance of license it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted license shall be cancelled;

#### Existing rule

- (ix) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the license then the license shall be cancelled. An employee of the Government shall also be ineligible to apply for the grant of license;
- (x) that in case of being selected as licensee, bank drafts of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited by him in the office of District Excise Officer within 48 hours after selection:
- (xi) that he has not made use of the bank drafts of earnest money in making application for any other shop in the same phase;
- (f) That he shall upload a scanned copy of bank draft of earnest money issued in favour of District Excise Officer of the district of the concerned shop along with online application as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government:
- (g) In case of being selected as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within 48 hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues;
- (h) That he is holder of solvency certificate or certificate of owned property issued by Income Tax valuer and the worth of solvency or certificate of owned property issued by Income Tax valuer shall be equivalent to not less than the amount of license fee determined for the grant of license of applied shop in the district. Licensees shall be required to submit the original copy of solvency certificate or certificate of owned property issued by Income Tax valuer in that district from where it has been issued at the time of grant of license:

#### Column-II

#### Rule as hereby substituted

- (ix) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the license then the license shall be cancelled. An employee of the Government shall also be ineligible to apply for the grant of license;
- (x) that in case of being selected as licensee, bank drafts of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited by him in the office of District Excise Officer within 48 hours after selection;
- (xi) that he has not made use of the bank drafts of earnest money in making application for any other shop in the same phase;
- (f) That he shall upload a scanned copy of bank draft of earnest money issued in favour of District Excise Officer of the district of the concerned shop along with online application as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government;
- (g) In case of being selected as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within 48 hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues;
- (h) That he is holder of solvency certificate or certificate of owned property issued by Income Tax valuer and the worth of solvency or certificate of owned property issued by Income Tax valuer shall be equivalent to not less than the amount of license fee determined for the grant of license of applied shop in the district. Licensees shall be required to submit the original copy of solvency certificate or certificate of owned property issued by Income Tax valuer in that district from where it has been issued at the time of grant of license:

## Existing rule

Provided, in case of renewal, solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.

#### Column-II

Rule as hereby substituted

Provided, in case of renewal, solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.

3. Amendment of rule 12–In the said rules, for existing rule 12 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted namely:—

#### Column-I

#### Existing rule

12-Payment of License fee and Security amount - In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of license fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through e-payment. Security amount shall be deposited through Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment:

# Provided, if he fails to deposit the amount of license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled:

#### Column-II

Rule as hereby substituted

12-Payment of License fee and Security amount - In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of license fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through e-payment. Security amount shall be deposited through Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment:

Provided that if the security amount is not deposited within the prescribed period, a penalty of Rs. 2000/- per day shall be imposed. Only a period of 15 days shall be allowed to deposit security amount along with penalty:

Provided, if he fails to deposit the amount of license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled:

#### Existing rule

Provided further that in case of licence being settled through the e-lottery/ e-tender, his earnest money and license fee as well as the security amount, if deposited by him, and in case of licence being renewed, fifteen percent of security amount of last year along with renewal fee and licence fee, if deposited by him, shall also be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government.

#### Column-II

#### Rule as hereby substituted

Provided further that in case of licence being settled through the e-lottery/ e-tender, his earnest money and license fee as well as the security amount, if deposited by him, and in case of licence being renewed, fifteen percent of security amount of last year along with renewal fee and licence fee, if deposited by him, shall also be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government.

4. Amendment of rule 20–In the said rules, for existing rule 20 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:—

#### Column-I

#### Existing rule

#### 20- Interim Settlement of shop-

(1) In case a license is suspended, cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules or if the shop remains unsettled for any reasons the licensing authority may make interim settlement of the shop at the highest offer on the payment of daily license fee on such rates as notified by the Excise Commissioner with the prior sanction of the Government and proportionate consideration fee (i.e. consideration involved in the daily minimum guaranteed quantity) for a maximum period of fourteen days at one stretch or till the date of regular settlement, whichever is earlier. In case of obtaining two or more equal offers for one shop, settlement shall be done through manual public lottery. Such licensee shall also be required to deposit security amount equivalent to 1/6th of the sum of consideration fee and license fee involved in the period of interim settlement. Such settlement of shop can be done more than twice by the licencing authority, but in such situation it will be essential to inform the Excise Commissioner.

#### Column-II

Rule as hereby substituted

#### 20- Interim Settlement of shop-

(1) In case a license is suspended, cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules or if the shop remains unsettled for any reasons the licensing authority may make interim settlement of the shop at the highest offer on the payment of daily license fee on such rates as notified by the Excise Commissioner with the prior sanction of the Government and proportionate consideration fee (i.e. consideration fee involved in the daily minimum guaranteed quantity) for a maximum period of fourteen days at one stretch or till the date of regular settlement, whichever is earlier. In case of obtaining two or more equal offers for one shop, settlement shall be done through manual public lottery. Such licensee shall also be required to deposit security amount equivalent to 1/6th of the sum of consideration fee and license fee involved in the period of interim settlement. Such settlement of shop can be done more than twice by the licencing authority, but in such situation it will be essential to inform the Excise Commissioner.

#### Existing rule

(2) In case any license is cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules, regular settlement of the shop shall be done as soon as possible by the Licensing Authority through the process of e-tender in mid-session after giving public advertisement. The intimation of aforesaid settlement shall be sent forthwith to the Excise Commissioner.

#### Column-II

#### Rule as hereby substituted

(2) In case any license is cancelled or accordance with surrendered in the provisions of these rules, regular settlement of the shop shall be done as soon as possible by the Licensing Authority through the process of e-tender in mid-session after giving public advertisement. Single tender shall also be accepted in the e-tender process for the shops to be settled in the mid-session. The intimation of aforesaid settlement shall be sent forthwith to the Excise Commissioner.

> Dr. Adarsh Singh, Excise Commissioner, Uttar Pradesh.